(b) whether it is also a fact that the M.P. Electricity Board wanted to mine coal, through the State Mining Corporation by which the mining profits would have gone to the Corporation but the mining lease application of the Corporation was rejected for village Bakohi, district Shahdol while Government of India is considering grant of a mining lease to the State Corporation of Assam Government; and

(c) if so, the reasons for this disparity?

The Minister of Mines and Metals (Shri S. K. Dey): (a) Exploitation of coal resources by the States is allowed if it is consistent with the all India policy and the development scheme forms an intergal part of the planned programme.

(b) and (c). In view of adequate production of non-coking coal in the country and its easy availability, it was considered that it would not be advisable grant fresh mining leases in this area. However, the matter is now being re-examined in consultation with the State Government. Proposal of the Government of Assam was approved mainly because of the local demand in the area and the transport difficulties.

Allocation of Tin for Small-Scale Industries

1021. Shri Shiva Dutt Upadhyaya:
Shri R. S. Pandey:
Shri Ulkey:
Shri A. S. Saigal:
Shri R. S. Tiwary:
Shri Chandak:
Shri J. P. Jyotishi:
Shri Wadiwa:

Will the Minister of **Industry** be pleased to state:

(a) whether a decrease of 22 per cent in the allocation of tin for the small-scale industries sector was made during the period April, 1963—September, 1963 as compared to October, 1962—March, 1963;

(b) whether this decrease was applied uniformly to all the States; and

(c) if not, what has been the basis?

The Minister of Industry (Shri D. Sanjivayya): (a) There was a decrease of about 14 percent in the allocation of tin for the small scale industries sector (including textile accessories units and the cashew nut industry) for the period April-September, 1963 as compared to the period October, 1962-March, 1963.

(b) Uniform reductions during April-September, 1963 were made in the allotment to the States as well as the Textile Accessories and Cashew nut industries after taking into account the requirements from Jammu & Kashmir which were received for the first time during April-September, 1963.

(c) Does not arise.

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग

1022. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग ने 1965 में खादी तथा ग्रामोद्योगों पर राज्यवार कितनी राशि खर्च की;

(ख) उस अवधि में आयोग ने राज्यवार कितनी सहायता दी; और

(ग) ग्रामीणों में खादी तथा ग्रामोद्योग उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री झफी कुरैशी): (क) विवरण नीचे दिया गया है :

विवरण

क्र० सं०	राज्य	किया गया खर्च (लाख रु०)
1.	आंध्र प्रदेश	3.05
2.	असम	0.85
3.	बिहार	0.89
4.	गुजरात	0.48
5.	जम्मू तथा काश्मीर	0.43
6.	केरल	1.14
7.	मध्य प्रदेश	1.28
8.	मद्रास	1.53
9.	महाराष्ट्र	1.44
10.	मैसूर	2.17
11.	उड़ीसा	0.74
12.	पंजाब	2.48
13.	राजस्थान	2.60
14.	उत्तर प्रदेश	3.94
15.	पश्चिमी बंगाल	1.81
16.	गोआ	0.08
17.	पहाड़ियां तथा सीमावर्ती क्षेत्र	8.48
	योग	33.39

(ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और यथासमय सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

(ग) (1) निःशुल्क बुनकर योजना चालू करना ।

(2) किस्म तथा परिमाण दोनों में सुधार करने के लिये उन्नत औजारों का प्रचलन ।

(3) स्वयं कातने वाले के लिये विशेष सहायता ।

उत्तर प्रदेश का निर्यात प्रोत्साहन निगम

1023. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश राज्य में एक निर्यात प्रोत्साहन निगम स्थापित करने के सम्बन्ध में वहां की सरकार ने केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों पर; और

(ग) इस निर्यात प्रोत्साहन निगम की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). जी, नहीं । ऐसा निगम स्थापित करने के लिये केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन की जरूरत नहीं होती । फिर भी हम ने इस प्रयत्न तथा निर्यात संवर्द्धन के इस कदम की प्रशंसा की है ।

(ग) उत्तर प्रदेश निर्यात निगम कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत 10-1-1966 को निगमित किया गया है । इसकी अधिकृत पूंजी 50 लाख रु० है जिसमें से 51 प्रतिशत उत्तर प्रदेश सरकार की होगी और शेष 49 प्रतिशत गैर-सरकारी हिस्सेदारों की होगी ।

निगम नीचे लिखे मुख्य उद्देश्यों के लिए स्थापित किया गया है ।

(i) उत्तर प्रदेश के मध्यम तथा लघु आकार पर चलने वाले उद्योगों की वस्तुओं को निर्यात बाजारों तक पहुंचाने के साधन का काम करना;